(ख) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के काली मिट्टी वाले जिला बांदा के लिए इस परियोजना का भारी महत्व है;

(ग) क्या यह भी सच है कि मध्य प्रदेश के वरियापुर बियर के बाएं तट से निकलने वाली नहर के लिए जल की आपूर्ति इसी परियोजना से संभव होगी; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस विवाद को निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

कृषि और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (घ) गंगऊ परियोजना के कार्यान्वित हो जाने पर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में जल की उपलब्धता में वृद्धि होगी। तथापि, मध्य प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच अंतर्राज्यीय मुद्दों के समाधान के बाद में इस परियोजना की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

उत्तर प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं

2632. **प्रो. रामबख्श सिंह वर्मा:**
श्रीमती मालती शर्मा:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश की अनेक सिंचाई परियोजनाएं सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृत कर लिया जायेगा;

(घ) इनके लिये कितनी धनराशि आबंटित की जायेगी; और

(ङ) इन परियोजनाओं को स्वीकृत किये जाने में विलम्ब के क्या कारण है?

कृषि और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (घ) विवरण अनुपत्र में दिया गया है [देखिए परिशिष्ट 186 अनुपत्र संख्या 47]

(ङ) परियोजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करेगी कि राज्य सरकार केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों को कितनी शीघ्रता से मानती है।

Central Assistance for Madduvalasa Project

2633. SHRI YERRA NARAYANA-SWAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether additional Central assistance has been sought by Andhra Pradesh Government for the Madduvalasa Project;

(b) if so, what is the additional Central assistance sought for this Project;

(c) the quantum of Central assistance released in this regard;

(d) whether the request of Andhra Pradesh Government has been complied with; and

(e) if not, status of the request?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND WATER RESOURCES (SHRI SOMPAL): (a) to (e) An amount of Rs. 14.34 crores was approved for Maduvalasa Project as requested by Andhra Pradesh in June, 1998 as Central Loan Assistance under Accelerated Irrigation Benefit Programme 1998-99. First instalment of Rs. 7.17 crores was released. Second Instalment was not released as State Government informed in November, 98 that they have reduced their budget for this project for 1998-99.

वैज्ञानिक जल प्रबंधन के लिए मास्टर प्लान

2634. **श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरदार सरोवर निगम ने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में वैज्ञानिक जल प्रबंधन के लिए कोई मास्टर प्लान तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त "मास्टर प्लान" की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या "मास्टर प्लान" के क्रियान्वयन में होने वाले व्यय का कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संसाधन जुटाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये है?

कृषि और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, नहीं। सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड, जो कि पूर्णत: गुजरात सरकार के स्वामित्व में है, को नर्मदा जल विवाद अधिकरण के पंचाट के अनुसार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के भागीदार राज्यों को लाभ देने वाले नर्मदा जल को काम में लाने के लिए गुजरात राज्य में सरदार परियोजना के क्रियान्वयन का कार्य सौंपा है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।